आरईसी REC
असीमित ऊर्जा, अनन्त संभावनाएं
Endless energy. Infinite possibilities.

G20 भारत 2023 INDIA

2030 तक 500 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता की प्राप्ति: सपना या हकीकत?

क्या हम एक ऐसी दुनिया की कल्पना कर सकते हैं जहां ऊर्जा से जुड़ी सभी जरूरतें नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों से पूरा होती हों? भारत 2023 में जी20 का अध्यक्ष है और यह पेरिस समझौते के प्रति अपनी सम्पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ रहा है। हमारा देश आज अपने ऊर्जा क्षेत्र को लेकर पहले से कहीं अधिक सजग हो गया है। यह महज संयोग नहीं है कि जी20 देशों में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जो अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और भविष्य के सपनों को पूरा करने के लिए सही राह पर आगे बढ़ रहा है।

नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता के मामले में भारत दुनिया में चौथे स्थान पर है और यह 2030 तक अपनी 40% बिजली उत्पादन क्षमता को गैर-जीवाश्म ईंधन से प्रतिस्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि उस समय तक 500 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य हासिल किया जा सके। हालाँकि, भारत के लिए एक अत्यंत उत्साहवर्धक आंकड़ा सामने आया है जिसके अनुसार 31 मार्च, 2022 तक भारत की स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 156 गीगावॉट हो गई है, जो कुल स्थापित बिजली क्षमता का लगभग 39% है।

इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाला देश होने के कारण भारत को अपनी घरेलू ऊर्जा की मांग पूरा करने में भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन, जब नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र की बात आती है तो इतने विविध और विशाल भू-भाग में फैली आबादी की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में भारत का अब तक का प्रदर्शन सराहनीय रहा है।

2030 की कार्य-योजना और सतत भविष्य की चिंताओं को देखते हुए, जी20 देशों को जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए प्रभावी ऊर्जा उद्देश्यों पर काम करना ही होगा। इस समूह का हिस्सा होने के नाते भारत नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र की वैश्विक हिस्सेदारी में योगदान करने के लिए निवेश की सुविधा प्रदान करने के साथ-साथ बाजार डिजाइन का विकल्प प्रदान करने, एकीकरण को बढ़ावा देने और बिजली क्षेत्र के अलावा अन्य क्षेत्रों की प्रगति में तेजी लाने के लिए काम रहा है। इसके अलावा, भारत अधिक ऊर्जा दक्ष नीतियों के लिए सहयोग को बढ़ाने तथा विभिन्न क्षेत्रों में निवेश में वृद्धि को प्रोत्साहन देने पर सहमत है।

इस बीच भारत ने हरित ऊर्जा क्षेत्र में अपनी गतिविधियों को और तेज कर दिया है, आरईसी का लक्ष्य सतत भविष्य पर अधिक जोर देते हुए इन रुझानों का लाभ उठाना है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए, आरईसी देश भर में सौर, पवन, बायोमास, ई-मोबिलिटी जैसी अनेक स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं के वित्तपोषण में आगे बढ़ी है। साथ ही, देश की अग्रणी महारत्न एनबीएफसी आरईसी नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के वित्तपोषण को बढ़ावा देने और बड़े पैमाने पर लोगों की जीवन शैली को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

आरईसी जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करते हुए पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के लक्ष्य के साथ भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के राष्ट्रीय दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ रही है। आरईसी विशेष ग्रीन बांड के माध्यम से पात्र परियोजनाओं के पुनर्वित्तीयन पर भी विचार कर रही है। आरईसी ने 'ग्रीन पोर्टफोलियो' बनाकर, निगरानी और नियमित जवाबदेही स्थापित करने के लिए एक सुस्थापित आंतरिक ट्रैकिंग प्रणाली के सक्षम प्रबंधन के लिए एक बेंचमार्क स्थापित किया है।

2011 से, आरईसी ने ₹84,100 करोड़ की ऋण सहायता और ₹1,36,600 करोड़ के पूंजी निवेश के साथ 16.5 गीगावॉट क्षमता वाली लगभग 244 परियोजनाओं को वित्तपोषित किया है। देश में हरित ऊर्जा की विशाल क्षमता को महसूस करते हुए, आरईसी ने टिकाऊ भविष्य की दिशा में आवश्यक बदलाव लाने के लिए आकर्षक वित्तपोषण शर्तों की पेशकश की है। आरईसी ने प्रमुख नवीकरणीय ऊर्जा हितधारकों जैसे रिन्यू पावर, एसीएमई ग्रुप, एवीएडीए, अदानी ग्रुप, जेएसडब्ल्यू ग्रुप, ईएनजीआईई, ओलेक्ट्रा, माइट्रा ग्रुप आदि के साथ मजबूत व्यापारिक संबंध बनाए हैं और रणनीतिक साझेदारी की है।

भारत में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को वित्त पोषित करने के लिए आरईसी ने एनबीडी (चीन) से 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर, केएफडब्ल्यू (जर्मनी) से 450 मिलियन यूरो और आईआईएफसीएल (यूके) से 147 मिलियन अमेरिकी डॉलर सफलतापूर्वक जुटाए हैं। इसलिए, यह माना जा सकता है कि भारत में जीवाश्म ईंधन से निरंतर बढ़ती ऊर्जा की मांग को पूरा करने में आरईसी की प्रभावशाली भूमिका है। जैसे-जैसे हम स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ेंगे और स्मार्ट ऊर्जा को जीवन जीने के तौर-तरीके के रूप में चुनने लगेंगे, हम एक स्थाई भविष्य के साथ एक बेहतर दुनिया के अपने सामूहिक सपने के और करीब पहुंच जाएंगे।